भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2469

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात

2469, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विनिर्मित और निर्यातित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत विशेषकर झारखंड में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले 5 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण और निर्यात, अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

करोड़ रूपये में

वित्तीय वर्ष	**विनिर्माण ***	**निर्यात #**
2019-20	533,550	71,556
2020-21	554,461	77,329
2021-22	640,810	60,395
2022-23	822,350	189,410
2023-24	952,000	241,171

स्रोत: * एमईआईटीवाई वार्षिक रिपोर्ट और उद्योग संघ, # डीजीसीआईएस

चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2024-25) में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 159,323 करोड़ रुपये का हुआ है।

(ख) से **(ग)** इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना: एमएआई योजना पात्र एजेंसियों को आवश्यक पहल और परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। ऐसी पहलों में निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना; नवाचार को बढ़ावा देना;व्यापार और बाजार आसूचना विकसित करना; उपयुक्त कौशल सेट का निर्माण करना; विदेशों में नए बाजारों की खोज के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों का हल करना शामिल है। सरकार भारतीय निर्यातकों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस योजना के तहत अनुदान सहायता प्रदान करती है।

सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित सभी वस्तुओं के निर्यात पर नियमित रूप से नज़र रखती है। निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), निर्यातकों, निर्माताओं और उद्योग संघों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उनके सामने आने वाली समस्याओं को समझा जा सके और उन्हें हल करने के तरीके खोजे जा सकें। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर व्यापार में बाधाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय मिशनों और विदेशी समकक्षों के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(घ) सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं:

1. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

2. आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई और आईटी हार्डवेयर 2.0

3. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना

4. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना और संशोधित ईएमसी योजना

5. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना

6. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि

7. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम

8. सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम

9. सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना की योजना

10. डिस्प्ले फ़ैब्स की स्थापना की योजना

11. कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाएं स्थापित करने की योजना और

12. डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, 100% एफडीआई, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट, प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी का सरल आयात, सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 और अनिवार्य पंजीकरण आदेश ने भी देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकास में सहायता की है।

(ड.) 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं, जिसके कारण कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां देश में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार कर रही हैं। ये पहलें झारखंड राज्य सहित पूरे भारत में की गई हैं।

एमईआईटीवाई की ईएमसी योजना के तहत झारखंड राज्य में लाभार्थी कंपनियों का विवरण:

क्र.सं.	**कंपनियों का नाम**	**उत्पाद**
1	अजंता रिफोस्टील केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	डिजिटल तापमान विश्लेषक, गर्म धातु तापमान विश्लेषक, आदि।
2	ई-वेस्ट रीसाइकिलर्स एलएलपी	औद्योगिक स्वचालन, ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण
3	श्री सहजानंद्स ऑटोमेक प्राइवेट लिमिटेड	रोबोटिक डस्ट सप्रेशन मिस्ट
4	सीटीसी प्रेजिशन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	टंगस्टन कार्बाइड/सिरेमिक उपकरण
5	प्रिबुसिन एलएलपी	सेंसर और ट्रांसमीटर, डिजिटल संकेतक, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर गेज
6	एकता टेली कम्युनिकेशन एंड सिस्टम्स	वायरलेस विमान उड़ान डेटा रिकॉर्डर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
7	ग्रीनवर्ल्ड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक
8	टी2 रियलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	पीसीबी, बैटरी चार्जर, कृषि उत्पादों के लिए नियंत्रण कार्ड आदि।
9	मीडिया मैजिक्स	एलईडी फ्रेम, एलईडी स्क्रीन, ग्लो साइन बोर्ड, एसीपी ऐक्रेलिक 3डी एलईडी बोर्ड

एमईआईटीवाई की योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी कंपनियाँ

1	आंध्र प्रदेश	31
2	असम	2
3	छत्तीसगढ	7
4	दादरा एवं नगर हवेली	1
5	दमन	1
6	दिल्ली	4
7	गोवा	9
8	गुजरात	42
9	हरियाणा	47
10	हिमाचल प्रदेश	9
11	झारखंड	9
12	कर्नाटक	58
13	केरल	9
14	मध्य प्रदेश	36
15	महाराष्ट्र	89
16	ओडिशा	3
17	पांडिचेरी	1
18	पंजाब	4
19	राजस्थान	57
20	तमिलनाडु	52
21	तेलंगाना	43
22	उत्तर प्रदेश	60
23	उत्तराखंड	5
24	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	**584**

******